(b) what is the actual amount spent on the Project during these years, year-wise and during 1990 till date;

(c) what is the overall estimated cost of the Project at the current prices by the close of the financial year 1990-91; and

(d) what is the present position with regard to the completion of the project stating the steps contemplated by the Central Government to accelerate the process of its completion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b)

Year	Budget Outlay for Canal works	Actual expenditure
	(Rs. Crores)	
1987-88 . .	65.00*	65.00
1988-89 . .	60.00*	52.64
1989-90 . . .	64.13*	56.94
1990-91 . . .	70.45* (upto June, 1990)	10.31

*(These figures are inclusive of the funds available under Border Area Development Grant)

The above does not include an expenditure of Rs. 111.87 crores during 1987-88 to 1989-90 and outlay of Rs. 65.78 crores during 1990-91 for CAD works.

(c) The State Government has not yet finalised the revised estimate at current prices including the command area development works.

(d) According to the State Government, the completion of the project is likely to extend to the Tenth Plan. During the Seventh Plan the Central Government provided a total assistance of Rs. 164.20 crores which is about 47 per cent of the total expenditure on Canal, and CAD works in that Plan on Stage-II.

Overdrafts by Tripura Government from R.B.I.

1015. SHRI NARAYAN KAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) The number of times Tripura Government resorted to overdrafts from R.B.I. in 1988 and 1989;

(b) The number of times Tripura Government resorted to overdrafts from R.B.I. in 1986 and 1987;

(c) The grounds for resorting to such frequent overdrafts; and

(d) whether the Central Government imposed any financial discipline against wasteful expenditure, if there was any?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) The Government of Tripura did not run into overdraft with the RBI during the financial years 1986-87 and 1987-88, but went into overdraft 10 times in 1988-89 and 13 times in 1989-90.

(c) Overdrafts arose mainly on account of the imbalances between the flow of receipts and pace of expenditure.

(d) According to the State Government, overdrafts were not due to wasteful expenditure and hence the question of Central Government imposing financial discipline against wasteful expenditure did not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात-लक्ष्य में कमी किया जाना

1016. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1990 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस" में "एस.टी.सी. पूल्स 90-91 टारगेट बाई रूपीज 450 करोड़स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1990-91 के लिए आरम्भ में राज्य व्यापार निगम का निर्यात लक्ष्य 1050 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लक्ष्य में गाद में कमी कर दी गयी थी; यदि हां, तो इसमें कितनी कमी की गयी थी ; और

(घ) उक्त निर्यात लक्ष्य में किन कारणों से कमी करनी पड़ी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। लक्ष्य में 580 करोड़ रुपये के स्तर तक कमी कर दी गयी थी।

(घ) एस.टी.सी. द्वारा निर्यात कम करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :—

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन और कुछ मदों का गैर-सरणीकरण ;

(ख) पूर्वी यूरोप का बाजार खुलने में परिवर्तन होने की वजह से जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य तथा अन्य देशों को चमड़े के निर्यात की धीमी गति ;

(ग) मसाला व्यापार निगम को मसाले का तथा एम.एम.टी.सी./पी.ई.सी. को कुछ इंजीनीयरी मदों का निर्यात सौंपा जाना ;

(घ) टी.टी.सी आई. द्वारा एस.टी.सी. की मार्फत चाय का निर्यात अपेक्षानुसार न होना ;

(ङ) ईराक से बंगलादेश को सीमेंट के निर्यात के लिए ईराकी संविदाओं का रद्द होना ;

(च) एस.टी.सी. को बजाय भारतीय व्यापारियों से प्रत्यक्ष रूप से चावल खरीदने का जी.सी.सी. का निर्णय ;

(छ) प्रति व्यापार निर्यात की कार्य विधि में परिवर्तन ।

विजाग इस्पात संयंत्र के लिए धन राशि उपलब्ध कराया जाना

1017. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई 1990 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "विजाग स्टील प्लांट रन्स इनटू रफ वेदर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आवश्यक धनराशि के अभाव में इस परियोजना को निर्धारित समानुसार पूरा नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई धनराशि को समय पर उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना को वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, इस परियोजना को पूरा किये जाने में विलम्ब के ये भी कारण हैं :—येलेरू हैं नहर के पूरा किये जाने में विलम्ब, विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से उपस्करों की सप्लाई और कुछ स्वदेशी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं का अपर्याप्त कार्य निष्पादन। पूंजीगत धन की कमी के कारण परियोजना को उसकी वित्तीय जरूरतों के लिए समय पर धन नहीं मिलता